



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43]
No. 43]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 1985/माघ 8, 1906
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 1985/MAGHA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)
अधिसूचना

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Heavy Industry)
NOTIFICATION

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1985

New Delhi, the 28th January, 1985

का. आ. 52(अ).—केन्द्रीय सरकार, हुगली डॉकिंग
एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और
अंतरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 55) की धारा
2 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—

S.O. 52(E).—In exercise of the powers conferred
by clause (h) of section 2 of the Hoogly Docking
and Engineering Company Limited (Acquisition and
Transfer of Undertakings) Act, 1984 (55 of 1984),
the Central Government hereby specifies :—

(क) तारीख 28 जनवरी, 1985 को, उक्त अधिनियम
की धारा 16 की उपधारा (1) के प्रयोजन के
लिए, तारीख के रूप में, और

(a) the 28th day of January, 1985, as the
date for the purpose of sub-section (1) of
section 16; and

(ख) तारीख 1 अप्रैल, 1985 को, उक्त अधिनियम की
धारा 18 के प्रयोजन के लिए, तारीख के रूप में,
विनिर्दिष्ट करती है।

(b) the 1st day of April, 1985, as the date
for the purpose of section 18 of the said
Act.

[फा० सं० 1 (43)/84-एच०ई II]

[File No. 1(43)/84-HE.II]

का. आ. 53(अ).—केन्द्रीय सरकार, हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 55) की धारा 31 की उपधारा (2) के खण्ड- (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) निधियों का प्रशासन नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 55) अभिप्रेत है।

(ख) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(ग) “भविष्य निधि” से मसर्स हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा उनके किसी उपक्रम में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए स्थापित की गई भविष्य निधि अभिप्रेत है।

3. निधियों का प्रशासन—ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से संबंधित, जिनकी सेवाएं अधिनियम द्वारा या उसके अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी विद्यमान, या नई सरकारी कंपनी को अंतरित हो गई है, किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, कल्याण निधि या किसी अन्य निधि में जमाखते कोई धन, नियत दिन से ही और ऐसे समय तक जब तक उनके प्रशासन या निष्पादन या दोनों के लिए कोई वैकल्पिक पद्धति निश्चित नहीं की जाती, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी द्वारा, नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, कल्याण निधि या किसी अन्य निधि को लागू नियमों, विनियमों और उप-विधियों या उन्हें प्रशासित करने वाली विधि के उपबंधों, उसमें ऐसे उपांतरणों सहित जो उक्त नियमों, विनियमों और उप-विधियों में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किए जाएं, के अनुसार बरता जाएगा।

[फा. सं. 1 (41)/84-एच. ई-II]

S.O. 53(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (b) of sub-section (2) of section 31 of the Hooghly Docking and Engineering Company Limited (Acquisition and Transfer Undertakings) Act, 1984 (55 of 1984), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Hooghly Docking and Engineering Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Administration of Funds Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires—

(a) ‘Act’ means the Hooghly Docking and Engineering Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1984 (55 of 1984);

(b) ‘Section’ means a section of the Act;

(c) ‘Provident fund’ means the Provident Fund established by Messrs Hooghly Docking and Engineering Company Limited for the benefit of persons employed in any of the undertakings owned by them.

3. Administration of Funds.—The monies standing to the credit of the provident fund, superannuation fund, welfare fund or any other fund relatable to the officers or other employees whose services have become transferred by or under the Act to the Central Government or an existing, or a new Government company shall, on and from the appointed day and till such time as alternative modes of their administration or disposition of both are formulated, be dealt with by the Central Government or the existing, or new, Government Company, as the case may be, in accordance with the provisions of the rules, regulations and bye-laws applicable to, or of any law governing the provident fund, superannuation fund, welfare fund or any other fund and its administration immediately before the appointed day, with such modifications as may be carried out in the said rules, regulations and bye-laws by the appropriate authority.

[File No. 1(41)/84-HE.II]

का. आ. 54(अ).—केन्द्रीय सरकार, हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 55) की धारा 31 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) (किसी सम्पत्ति के बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित से संबंधित संसूचना) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण)

अधिनियम, 1984 (1984 का 55) अभिप्रेत है;

(ख) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. संसूचना के लिए समय की परिसीमा—किसी ऐसी संपत्ति का जो अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार में या किसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गई है, प्रत्येक बंधकदार और किसी ऐसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई भार धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आयुक्त को ऐसे बंधक, भार धारणाधिकार या अन्य हित की संसूचना ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 18 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए, तीस दिन की अवधि के भीतर देगा।

परन्तु यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि बंधकदार या कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला व्यक्ति तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर संसूचना देने से पर्याप्त हेतुक के कारण निवारित हो गया था तो वह ऐसे कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर संसूचना प्राप्त कर सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नहीं।

4. संसूचना की रीति —(1) नियम 3 के अधीन आयुक्त को दी जाने वाली प्रत्येक संसूचना लिखित में होगी और आयुक्त को संबोधित होगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्—

(क) बंधकदार का या किसी ऐसी संपत्ति में या उसके संबंध में भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति का नाम, विवरण और पूरा पता;

(ख) ऐसे उपक्रम का नाम जिसके संबंध में दावा किया गया है;

(ग) दावे की रकम (भारतीय करेंसी में);

(घ) यदि कोई लिखत हो तो उसकी विशिष्टियां, जिसके द्वारा बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित प्रतिभूत किया गया है, जो लिखत की अनु-प्रमाणित प्रति द्वारा समर्थित होगा;

(ङ.) पहले ही से प्राप्त रकम, यदि कोई हो, और उसकी विशिष्टियां;

(च) दावे से सुसंगत कोई अन्य विशिष्टियां;

(छ) अनुतोष जिसका दावा किया गया है;

(2) प्रत्येक संसूचना बंधकदार द्वारा या भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी।

(3) संसूचनाएं, सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय समय के दौरान 15 गणेश चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता-700013 स्थित आयुक्त के कार्यालय में फाइल की जा सकेंगी या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा आयुक्त को भेजी जा सकेंगी।

[फा. सं. 1 (40)/84-एच. ई.-II]

जी०एस० ग्रेवाल, संयुक्त सचिव

S.O. 54(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (a) of sub-section (2) of section 31 of the Hooghly Docking and Engineering Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1984 (55 of 1984), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Hooghly Docking and Engineering Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) (Intimation regarding Mortgage, Charge, Lien or other Interest in any Property) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) 'Act' means the Hooghly Docking and Engineering Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings), 1984 (55 of 1984).

(b) 'Section' means a section of the Act.

(c) all other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Time limit for intimation.—Every mortgagee of any property which has vested under the Act in the Central Government or in an existing, or a new Government Company, as the case may be, and every person holding any charge, lien or other interest in, or in relation to, any such property shall give intimation of such mortgage, charge, lien or other interest to the Commissioner within a period of thirty days from such date, as may be specified by the Central Government under section 18.

Provided that if the Commissioner is satisfied that the mortgagee or the person holding any charge, lien or other interest was prevented by sufficient cause from giving the intimation within the said period of thirty days, he may, after recording reasons in writing receive the intimation within a further period of thirty days and not thereafter.

4. Manner of intimation.—(1) Every intimation to be given to the Commissioner under rule 3 shall be in writing addressed to the Commissioner and shall contain the following particulars namely :—

- (a) Name, description and full address of the mortgagee or the person holding charge, lien or other interest in or in relation to such property.
- (b) name of the undertaking in respect of which the claim made;
- (c) amount of claim (in Indian currency);
- (d) particulars of the instrument, if any, by which the mortgage, charge, lien or other interest is secured; supported by an attested copy of the instrument;

(e) amount, if any, already received, with particulars;

(f) any other particulars relevant to the claim;

(g) relief claimed;

(2) Every intimation shall be duly signed and verified by the mortgagee, or the person holding the charge, lien or other interest or by a person duly authorised by him.

(3) Intimations may be filed in the office of the Commissioner at 15, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta—700013 on all working days during office hours or may be sent to the Commissioner by registered post with acknowledgement due.

[File No. 1(40)/84 HE. II]

G. S. GREWAL, Jt. Secy.